भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1270
उत्तर देने की तारीख 6 दिसंबर, 2021 (सोमवार)
15 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रश्न

मेक इन नॉर्थ-ईस्ट पहल

1270. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा मेक इन नॉर्थ-ईस्ट पहल के रूप में मेक इन इंडिया की नवोन्मेषी नीति पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें सरकार के विचाराधीन प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाया गया है;
(ग) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक व्यापक पर्यटन योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत एक समर्पित पूर्वोत्तर डेस्क स्थापित किया गया है जो निवेशकों तक पहुंचने की गतिविधियों के साथ-साथ चुनिंदा कंपनियों को मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान करने में पूर्वोत्तर राज्यों की सहायता करता है। यह डेस्क एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), स्टार्टअप और इस क्षेत्र में विभिन्न पहलों के लिए इन्वेस्ट इंडिया के अन्य क्षेत्र डेस्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में निवेश के अवसर पेश करने वाले इन्वेस्ट नॉर्थईस्ट पोर्टल को भी विकसित किया गया है।

उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 पांच वर्षों की अवधि के लिए 01.04.2017 से लागू है। यह स्कीम सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सभी राज्यों के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को कवर करती है। इस स्कीम के तहत प्रदान किए गए विभिन्न लाभों में शामिल हैं: (i) ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन; (ii) केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन; (iii) केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन; (iv) आयकर प्रतिपूर्ति; (v) वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति; (vi) रोजगार प्रोत्साहन और (vii) परिवहन प्रोत्साहन। संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधीन सभी घटकों के तहत लाभ के लिए 200 करोड़ रुपये प्रति यूनिट की कुल सीमा है। अक्टूबर 2021 के अंत तक, एनईआईडीएस के तहत 2,631.19 करोड़ रुपये के प्रस्तावित

कुल निवेश के साथ कुल 391 नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण प्रदान किया गया है। इन औद्योगिक इकाइयों के लिए कुल संभावित प्रोत्साहन 1,740.06 करोड़ रुपये है।

नीति आयोग के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित, समावेशी और सतत विकास के लिए गठित 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' ने चाय, पर्यटन, बांस, डेयरी और मछलीपालन जैसे 5 फोकस क्षेत्रों की पहचान की है।

(ग) और (घ) सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास और संवर्धन पर विशेष जोर दे रही है। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत विरासत, वन्यजीव, आध्यात्मिक, जनजातीय, ईको एडवेंचर आदि विषयों वाली सोलह परियोजनाओं को 1,337.63 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ स्वीकृत किया गया है। तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) स्कीम के तहत कामाख्या देवी मंदिर (29.99 करोड़ रुपये), नागालैंड में तीर्थयात्रा सुविधा (25.26 करोड़ रुपये) और मेघालय (29.31 करोड़ रुपये) के विकास को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क (असम) की पहचान आइकॉनिक साइट डेवलपमेंट स्कीम के तहत की गई है।

(ङ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न स्कीमों जैसे अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम और इसकी उत्तराधिकारी उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस), पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्कीमों और उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) के तहत भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक और भौतिक अवसंरचना की कमियों को पाटने के लिए कदम उठाए हैं, जिनसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एनएलसीपीआर-राज्य स्कीम के तहत 16,233.78 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1,635 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 9,424.11 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,194 परियोजनाएं अगस्त 2021 के अंत तक पूरी हो चुकी हैं। एनईएसआईडीएस के तहत अगस्त, 2021 के अंत तक 2,503.39 करोड़ रुपये की 104 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एनईसी, एनईआरएसडीएस और एनएलसीपीआर-केंद्र के तहत 7,849.78 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ कुल 610 परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनके लिए 5,916.71 करोड़ रुपये अगस्त 2021 के अंत तक जारी किए गए हैं।

इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में उनके सतत विकास के लिए विभिन्न अखिल भारतीय स्कीमें जैसे जल जीवन मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि चलाई जा रही हैं। डीपीआईआईटी के तहत इन्वेस्ट इंडिया के पूर्वोत्तर डेस्क ने इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संघों के सहयोग से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और व्यापार सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

*****